भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3664
जिसका उत्तर मंगलवार 11 अगस्त, 2015 को दिया जाना है

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण**

**3664. श्री मोहिते पाटील विजयसिंह शंकरराव:**

**श्रीमती सुप्रिया सुले:**

**श्री धनंजय महाडीक:**

**डॉ० हिना विजयकुमार गावीत:**

**श्री राजीव सातव:**

**श्री टी० राधाकृष्णन:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण में सभी सरकारी क्षेत्र उपक्रमों को 'कौशल भारत' प्रयास के अंतर्गत मोड्यूल तैयार करने और अपने संबंधित क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उन सरकारी क्षेत्र उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने दोनों, मशीनरी पर पारंपरिक प्रशिक्षण और कंप्यूटर पर आधुनिक प्रशिक्षण हेतु अपने प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ किए हैं;

(ग) सरकारी क्षेत्र उपक्रमों द्वारा युवाओं को वार्षिक आधार पर कौशल प्रदान करने के लिए निर्धारित लक्ष्य और प्रयोजन हेतु आवंटित निधियां कितनी हैं; और

(घ) सरकार द्वारा निर्धारित एक वर्ष में 24 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए गए हैं?

**उत्तर**
**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री**
**(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)**

**(क) और (ख):** भारी उद्योग विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों को उनके संबंधित क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का निदेश दिया गया है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स एंड इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, एन्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड और सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम, सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम, स्ट्रेटेजिक प्रबंधन कार्यक्रम, युवा प्रबंधक कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन, इंस्ट्रूमेन्ट स्तर पर टेस्ट रिपेयर, प्रिंटिड सर्किट बोर्ड, केबल्स, विद्युत आपूर्ति को टेस्ट और रिपेयर, मोबाइल रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग, रेफ्रिजरेशन तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जावा, सी++, डॉट नेट, विजुअल बेसिक, एमएस एसक्यूएल, ओरेकल, एमएस ऑफिस आदि जैसे विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

**(ग) और (घ):** राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद द्वारा भारी उद्योग विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वर्ष 2015-16 में 40,000 व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य दिया गया है। तथापि, इस परियोजनार्थ इस विभाग से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पृथक निधियां आबंटित नहीं की गई हैं। कौशल विकास के प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने हेतु निष्पादन की मॉनिटरिंग मासिक तथा तिमाही आधार पर की जाती है।

******